के प्रवधानों और उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। देश में खनन कार्य ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों की कंपनियों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1994-95 के अन्त तक कुल 3083 (अनन्तिम) खानों में से जो गैर परमाणु और गैर-ईंधन खनिजों और गौण खनिजों से इतर अन्य खनिजों का उत्पादन कर रही है, 316 निजी क्षेत्र में थीं। खान-और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अनुसार खनन अधिकार केवल किसी भारतीय राष्ट्रीक या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा (3) की उपधारा (1) में परिभाषित कंपनी को ही दिये जा सकते हैं। लेकिन प्रथम अनुसूची में विनिद्रिर्ष्ट किसी खनिज के लिए कोई भी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रदान नहीं किया जायेगा।

गुजरात में खनिजों की उपलब्धता का पता लगाने हेतु कार्य-योजना

3104. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किछ

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गुजरात राज्य में खनिजों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए एक कार्य योजना पर विचार किया है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ एक कार्य बल का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य बल की क्या-क्या उपलब्धि है; और

(घ) वर्तमान कार्य योजना में अंतर्ग्रस्त व्यय का ब्यौरा क्या हैय़

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बिरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

I. जी, नहीं। तथापि, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गुजरात सहित देश के खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए खनिज अन्वेषण ओर इससे संबंधित अन्य कार्य जारी कार्यक्रमों के रूप में कर रहा है।

II. भारत सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य दल गठित नहीं किया है।

III. और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Imports of Phosphates from Nauru Island

3105. SHRI SURINDER KUAMR SINGLA: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether India still imports phosphates from the Nauru Island in the Pacific;

(b) if so, the unit cost of phosphate being imported and how does it compare with the indegenous phosphates;

(c) for how many years more do we have have lease of phosphate mines, if any in Nauru; and

(d) the steps being taken to bring self sufficiency in phospates?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा गुजरात में खनन

3106 **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने गुजरात के कुछ जिलों में खनन आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी परियोजना का कार्य रोक दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(च) क्या निगम ने कुछ परियोजनाएं निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है;

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ज) निगम को अब तक हुए लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(b) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

VI. किसी परियोजना के गुजरात राज्य में किसी निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय नहीं लिया गया है।

VII. प्रश्न नहीं उठता।

विगत 3 वर्षों के दौरान मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अर्जित कर से पूर्व लाभों का ब्यौरा

नीचे दिया गया है:-

1994-95	10168.41 लाख रु.
1995-96	15045.51 लाख रु.
1996-97	16789.00लाख रु. अनंतिम)

Production of Rare or Scarce Metals

3107. DR. GOPALRAO VITHALRAO PATIL: Will the Minsiter of MINES be pleased
to state:

(e) the production of rare of scarce metals like copper, magnesium, selenium. Uranium, thorium, menganese and others which are used in new technologies; and

(f) whether the production of these metals is sufficient to fulfill the needs of our country?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Effect of the Recent Supreme Court Judgement of Mines in Forest Land

3108. SHRI V. RAJESHWAR RAO: Will
the Minister of MINES be pleased to state:

(b) Whether the mines presently in the forest land will be affected by the recent Supreme Court judgement to stop any non forest activity in forest land;

(c) if so, what will the Government do the save these mines; and

(d) what is the bearing of the judgement on the Mines?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) to (c) As per Forest (Conservation) Act, 1980 prior approval of Central Government is required before commencement for any non-forest activities in forest land.

The Hon'ble Supreme Court of India in its Interim Order dated 12.12.96 in the matter of Write Petition (Civil) No. 202 of 1995 has directed that in accordance with Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, all on going non-forest activities within any forest in any State through out the country without prior approval of the Central Government must cease forthwith.

Mining being a non-forest activity prior approval of the Central Government is required before undertaking mining in a forest area. For disposal of the applications seeking permission required under Forest (Conservaction) Act, 1980, the Hon'ble Supreme Court in its order dated 4.3.97 has directed that:

(c) Where the lessee has not forwarded the particulars for seeking permission under the Forest (Conservation) Act, 1980, he may do so immediately:

(d) the State Government shall forward all complete pending applications within a period of 2 weeks to the Central Government for requisite decisions: to the Central Government for requisite decisions:

(e) applications received (or completed) hereafter would be forwarded within two weeks of their being so made.

(f) the Central Government shall dispose of all such applications within six weeks of their being received. Where the grant of final clearance is delayed, the Central Government may consider the grant of working permissions as per existing practice.

Exports of Granite

3109. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) the names of the places in Madhya Pradesh, where mining work of granite is going on;

(b) whether exports of granite had been made from the state during the last three years;

(c) if so, the year-wise details thereof;

(d) the names of the countries to which export were made and the year-wise details of foreign exchange earned thereof; and

(e) the details of the programmes formulated by Government for the development of mining area of granite in the State?